श्री कमलापति त्रिपाठी : माननीय सदस्य के सुझाव बड़े अच्छे हैं । मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा क्योंकि दुर्घटनाओं से जहाजों को बचाने के लिये या किसी का भी प्राण बचाने के लिये हमेशा ही प्रबन्ध करना चाहिये । जो कुछ भी प्रबन्ध सम्भव हो और हो सकेगा उसके विषय में कई सुझाव आये हैं हम जरूर उस पर विचार करेंगे ।

जहां तक इन 6 आदमियों की खोज की बात है मैंने यह निवेदन किया कि मेरे पास आज सूचना यह आई है कि उन लोगों की खोज का काम बन्द कर दिया और अभी राव साहब को मैं जवाब दे रहा था कि मैं इस बात को देखूंगा कि क्यों खोज का काम बन्द कर दिया । अगर जिन्दा नहीं मिल सकते तो क्या यह सम्भव है कि उनके शव ही मिल जाय, यह मैं देखूंगा, इसकी जानकारी उनसे हासिल करूंगा । सम्भवतः उन्होंने यह समझ कर छोड़ दिया कि चार पांच दिन बराबर खोज करते रहे, कुछ पता नहीं लगा सका, जो मिल सके उनको ले आये जीवित या मृत और जो नहीं मिल सके उनके लिये ज्यादा परिश्रम और प्रयास करने का कदाचित कोई ज्यादा उपयोग नहीं होगा इसलिये उन्होंने छोड़ दिया होगा । फिर भी मैं उसकी जांच करूंगा ।

माननीय मधु जी ने जो सुझाव दिये उन्हें मैंने नोट कर लिया है । मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा कि कुछ किया जा सकता है तो किया जाय ।

जहां तक दूसरे देशों को मिलाकर कोई संगठन खड़ा करने की बात है वह तो एक अलग बात है । बंगला देश, मलाया और बर्मा ये सब स्वतन्त्र देश हैं । इनसे कुछ बातचीत करने के बाद ही कि कैसे किया जाय, क्या हो, ये ऐसे मसले हैं कि जिन पर विचार करने के बाद ही कुछ उत्तर दिया जा सकता है ।

12.38 hrs.

RE. ADJOURNMENT MOTIONS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir I have given notice of an Adjournment Motion. I want to make a statement. I have given notice of that also. (*Interruption*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । महाराष्ट्र और मैसूर का सीमा विवाद हल करने में केन्द्र सरकार की विफलता के कारण दोनों प्रदेशों में इस समय अशान्ति मची हुई है । पहले बेलगांव में मराठी भाषा भाषियों पर पुलिस ने ज्यादतियां कीं । अब उसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के कुछ भागों में हो रही है । यह मामला इतने सालों से पड़ा हुआ है । आखिर केन्द्र सरकार कोई निर्णय इसमें क्यों नहीं कर सकती ? मैसूर में भी कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है । केन्द्र में प्रधान मंत्री सारी सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित किये हुये हैं । यह सीमा विवाद कब तक लटका कर रखा जाय ? .....

श्री मधु लिमये (बांका) : हम लोगों के भी कामरोको प्रस्ताव हैं । क्या ये लोग को विघटन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या दो प्रदेशों में लड़ाई कराने का इनका इरादा है ?

श्री मधु लिमये : हमारे कामरोको प्रस्ताव पर तुरन्त बहस होनी चाहिये । सरकार की यह विफलता है राष्ट्र विघटन के कगार पर खड़ा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय , मेरा निवेदन है कि आप केवल इस आधार पर हमारे कामरोको प्रस्ताव को

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

स्वीकार न करें कि यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि अभी जो घटनायें—कोल्हापुर, बेलगांव या बम्बई में हुई है, उनके आधार पर स्वीकार करें—ये तात्कालिक घटनायें हैं ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Kindly allow me to read my motion: 'Government's failure in curbing communalism and regionalism as witnessed by the events in Greater Bombay, Kolhapur... (*Interruptions*). Then, there have been communal riots in Meerut, Allahabad and other towns. Then there is this Shiva Sena communalism and regionalism in Bombay. What is this Government doing?

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : "नफिया" का हैडक्वार्टर्स हिन्दुस्तान में आ गया है—इस पर अभी विचार होना जरूरी है ।

MR. SPEAKER: Kindly resume inter-State matter.

I do not deny that this matter is very important. This is a very important matter. I do not deny any chances of discussion on it. But, as an adjournment motion, I have studied it thoroughly. This matter has continued since a week.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): But eruption of violence is a recent phenomenon.

MR. SPEAKER: This was the same matter. Mr Dandavate was allowed a week before last week; and last week, on the same eruption of violence, Mr Dhamankar and Mr Nimbalkar also spoke. I do not deny any opportunity for discussion of debate on it. I will welcome it. I have received a number of call attention motions on it. Would you like a call attention or a separate discussion?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: No call attention. Only an adjournment motion.

MR. SPEAKER: An adjournment motion is not admissible on it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, एडमिसिबिलिटी के बारे में मेरी आपसे प्रर्थना है—कितनी हिंसा होने के बाद कितनी सम्पत्ति को जला डालने के बाद आप उसको सरकार का फेल्योर मानेंगे । आज देश बिल्कुल विघटन के कगार पर खड़ा है, यह केवल कर्नाटक या महाराष्ट्र का मामला नहीं है, समूचे देश में इसका विस्फोट हो रहा है—आप उसको फेल्योर मानेंगे या नहीं । इस मामले को लटकाये रख कर सरकार ने देश के साथ अन्याय किया है, आज देश टूट रहा है, मुल्क बिखर रहा है, इसलिये इस पर तुरन्त विचार होना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा कहना यह है कि यह मामला बहुत सालों से चल रहा है, इसलिये आप इसको स्वीकार न करें—यह तर्कसंगत बात नहीं है । सीमा विवाद को हल करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, यदि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी के पालन में विफल रहती है और उसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसक होती है—बम्बई में उद्दीपी होटलों पर हमले हो रहे है, हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं—इसलिये आप इस काल-ऐटेन्शन को को मंजूर करेंगे तो उससे समस्या हल नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अभी 10—12 दिन ये आप सरकार के खिलाफ नो-कान्फिडेन्स का मोशन लाये थे ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Shall we passively look at the whole situation when people are being murdered and their houses are being burnt?

MR. SPEAKER: If it concerns the riots, then it is a question of law and order for those States.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: No, Sir.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is an inter-State matter.

MR. SPEAKER: On the boundary dispute and even on this riot, there was a reference last week and a week before. This is not an urgent matter which suddenly arose; this is a continuing matter. The law and order position of a State cannot come here.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My Adjournment Motion states two things. One is this. The country is in the grip of serious regionalism and communalism. What is happening now, Sir, due to Shiv Sena violent agitations have taken place. There are violent riots in Greater Bombay, and South Indians are being suppressed and repressed. In Meerut and Allahabad serious communal riots have taken place. The figures have been given as regards U.P.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Large-scale violence has taken place there. Many South Indian hotels have been looted in Maharashtra. We are also agitated. There have been serious violence and arson.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Then you should support this djournment Motion.

SHRI K. LAKKAPPA: Not Adjournment Motion. We want a full-fledged, full-scale discussion.

MR. SPEAKER: Kindly sit down. It is said, Kannadigas are being beaten by Maharashtrians. It is a matter for the State administration.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, it is an inter-State matter. Regionalism is let loose in Maharashtra. This is an inter-State subject. We want a full discussion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Communal riots have been there in Meerut and In Allahabad. This is Centre"s responsibilty. They have given figures about U.P. They have admitted that in U.P. communal riots have gone up last year compared to the previous year.

MR. SPEAKER: So far as discussion is concerned, I may say, I am admitting a Calling Attention Motion on it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I am completely in agreement with friends from Mysore, and whether the atrocities have been committed on minorities either in Mysore or in Maharashtra, such incidents are condemnable. This is a matter relating to national integration and therefore the responsibility lies on the Centre. It is the failure of the Centre. Therefore, Adjournment Motion should be admitted. This is my respectful submission.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, let me make it clear that I don't subscribe to the views of Mr. Dandavate. I would like to say that these things are going on in Maharashtra. It is an inter-State affair. This may be discussed fully here. I do not want to subscribe to the views of Mr. Dandavate. The Shiv Sena forces are working and they are attaching the Kannadigas. Let there be a discussion here.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): You kindly gave permission to Prof. Dandavate and another hon. Member from the ruling party. Under Rule 377 they made a submission but no reply has come from the Minister. Had he made a statement, this Adjournment Motion would not have come, Sir. I want a discussion on this.

SHRI P. R. SHENOY (Udipi): *rose.*

MR. SPEAKER: Mr. Shenoy, kindly listen to me. I had already admitted a calling attention motion on it. Now you want also a discussion under Rule 193.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, Yes,

श्री मधु लिमये : जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता है ।

MR. SPEAKER: Shri Limaye, I want to see some time a broad smile on your face also! All the time you are in a tense mood.

We shall fix the debate on it. The calling attention fixed for tomorrow, will, of course, not come. We will have a discussion on it. You will tell me what time will suit for this purpose. This evening, there is a lot of work.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फूड कारपोरेशन वाली चर्चा टाली जा सकती है । यह अर्जेन्ट मामला है इसलिये आज इस पर बहस हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपकी सहूलियत के लिये रखा था ।

Mr. Shenoy, I shall certainly give you an opportunity. Don't get up everytime when I am standing.

On the suggestion of Shri Vajpayee —because he has got to catch some train on some urgent work—I advance the discussion on the Food Corporation from 4 P.M. to 3.30 P.M. But, if you want to stay on, then I can adjust the programme.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It would be done tomorrow. We have to make a study.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This is about the discussion on Food Corporation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: That is all right.

MR. SPEAKER: How will you be able to come tomorrow, Mr. Vajpayee? You better cancel your programme.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा कहना है कि महाराष्ट्र, मैसूर वाला मामला आज आ सकता है और फूड कारपोरेशन की चर्चा हम आगे ले जा सकते हैं ।

MR. SPEAKER: So, tomorrow evening we shall have this discussion. But, the discussion on Food Corporation will be at 3.30 P.M.

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र, मैसूर सीमा विवाद के सम्बन्ध में आपने विरोधी दलों के सदस्यों को मौका दिया लेकिन इधर के कुछ सदस्य दस बार खड़े हुये फिर भी उनको मौका नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं लाते हैं एडजर्नमेंट मोशन, आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री शंकर दयालसिंह : दोनों पक्ष के लोगों को मौका देना चाहिये । एक ही तरफ के लोग मौका ले लेते हैं और दूसरे विचारों के लोगों कुछ कहने से वंचित रह जाते हैं । और अखबारों से ऐसा लगता है कि जनता की समस्याओं से यही लोग चिन्तित है । (**व्यवधान**) इस सीमा विवाद में विरोधी दलों का हाथ रहा है (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैं इन अखबारों का खण्डन करता हूं । केन्द्रीय सरकार ने सीमा विवाद हल नहीं किया और ये विरोधी दलों पर आरोप लगा रहे हैं । यह आरोप नितान्त असत्य और शरारतपूर्ण हैं । सरकार की विफलता का दोष यह विरोधी दलों पर लगा रहे हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : इसमें कुछ राजनीतिक दलों का हाथ रहा है । आप कृपा करके इस पर बहस मत बढ़ाइये वरना यह बात साबित हो जायेगी (**व्यवधान**) . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, शाहदरा के दंगे की जांच हो गई है, हमने कहा कि रिपोर्ट मेज पर रख दी जाये लेकिन वह नहीं रखी जा रही है । मेरठ में जो दंगा हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिये ।

12.56 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER ALL-INDIA SERVICES ACT.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA):

I beg to lay on the Table:—

A copy of Notification No. G.S.R. 1278 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st December, 1973, containing Corrigenda to Notification No. G.S.R. 433(E) dated the 9th October, 1972, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-5973/73].

12.55½ hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Condct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 10th December, 1973 agreed without any amendment to the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking over of Management) Bill, 1973, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th December, 1973."

12.56 hrs.

RE ALLEGED FAILURE OF U.P. GOVERNOR TO SUMMON THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): Having considered the points raised by hon. Members yesterday with regard to the alleged failure of the Governor of UP to summon the ssembly within a period of six months, I have to make this submission that there has been no contravention or no violation of any constitutional provision.

Two articles are directly concerned in our coming to a decision on this matter. One is article 174(1) and the other is article 356. Both will have to be read together and in harmony. Article 174(1) does two things. It enjoins on the Governor to call the Assembly, and it also enjoins that the Assembly should be called within a specified period of six months, the period beginning from the last day of the last session and the beginning of the first day of the next session. But as I had said, article 174 also confers a power on the Governor to summon the Assembly, without which power be could not have summoned the Assembly. That is where article 356 in my submission comes in for consideration.

It is not necessary to refer to the whole of article 356 because amongst other matters there are two matters which are important and relevant for the present purpose. One is that by the Presidential Proclamation under article 356, he can declare that the powers of the legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, and secondly